शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 24 – 31 अगस्त 2026 मूल्य पांच रूपये

चुनावी साल में खुलेंगी भ्रष्टाचार की फाइलें या फिर चार्जशीटों तक सिमट जाएगी सियासत?

सुधीर शर्मा और जनक राज पर विजिलेंस कारवाई से गरमाया माहौल पुराने आरोपों पर कारवाई की परीक्षा, भाजपा – कांग्रेस आमने – सामने

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले सियासत का तापमान बढ़ने लगा है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा और भरमौर विधायक जनक राज से जुड़े विजिलेंस मामलों ने उस राजनीतिक लड़ाई को नया मुद्दा दे दिया है, जिसकी जमीन पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार, जमीन सौदों, भर्ती और सरकारी फैसलों में कथित अनियमितताओं के आरोपों से तैयार होती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है, बल्कि यह है कि क्या चुनावी वर्ष में आरोपों की फाइलें वास्तव में जांच और कारवाई के अगले चरण तक पहुंचेंगी या हिमाचल की राजनीति एक बार फिर चार्जशीटों और प्रेस कांफ्रेंसों के घेरे में ही घूमती रहेगी?

सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में विजिलेंस कारवाई ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया है। क्या आने वाले दिनों में सरकार पुराने मामलों में जांच आगे बढ़ाती है? सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं को लेकर चार्जशीट जारी की थी। चुनावी मंचों पर इन आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाया गया और सत्ता में आने के बाद कारवाई का भरोसा भी दिया गया।

चार साल के कार्यकाल पुरा होने को है अब जनता जानना चाहती है कि उन आरोपों में कितने मामलों में जांच हुई, कितने मामलों में एफआईआर हुई और कितने मामले अदालत तक पहुंचे? यहीं से कांग्रेस सरकार की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। चार्जशीट में लगाए गए आरोप यदि सही थे तो उन पर अब तक क्या कारवाई हुई है? और यदि कारवाई नहीं हुई तो क्या वे आरोप केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा थे?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल में सरकार बदलने के साथ आरोपों की दिशा भी बदलती रही है। विपक्ष में रहते हुए हर पार्टी सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाती है, सत्ता में आने के बाद जांच का भरोसा देती है और फिर अगला चुनाव आते-आते वही मुद्दे राजनीतिक भाषणों में दोबारा लौट आते हैं।

दूसरी ओर विपक्ष अधूरी गारंटियां, बढ़ता वित्तीय दबाव, रोजगार, भर्ती प्रक्रियाएं और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन भाजपा के सामने भी यह सवाल रहेगा कि वह केवल आरोप लगाएगी या जिन मामलों को गंभीर बता रही है, उन्हें दस्तावेजों के साथ जनता के सामने रखकर कानूनी कारवाई की मांग भी करेगी?

विपक्ष के लिए आने वाला वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल सरकार की आलोचना से चुनावी माहौल नहीं बनेगा। उसे यह बताना होगा कि किस मामले में क्या अनियमितता हुई, किसके खिलाफ क्या दस्तावेज हैं और सरकार से किस कारवाई की मांग की जा रही है। भाजपा को भ्रष्टाचार के आरोपों पर ब्यानबाजी कर इसका फायदा आने वाले चुनाव में तभी मिल पायेगा जब वह दस्तावेजी प्रमाण जनता के सामने रख पायेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से जुड़े जमीन संबंधी आरोप भी विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री इन आरोपों को खारिज कर अपना पक्ष विधानसभा में रख चुके हैं। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक बयानबाजी से नहीं निकलेगा बल्कि निष्पक्ष जांच एजैंसियों द्वारा करवाई गयी जांच के निर्णय से निकलेगा। चुनावी राजनीति में जमीन और संपत्ति से जुड़े आरोपों का असर गहरा होता है।

भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा रोजगार के मोर्चे पर होगी। चुनाव के समय किए गए रोजगार संबंधी वादे अब सरकार के चार साल पूरे होने के साथ विपक्ष के निशाने पर हैं। प्रदेश का युवा सरकारी भर्ती, परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों को लेकर स्पष्ट परिणाम चाहता है। यदि सरकार आने वाले एक साल में रोजगार और भर्ती के मोर्चे पर ठोस उपलब्धियां दिखाने में सफल रहती है तो वह विपक्ष के हमले की धार कम कर सकती है। लेकिन यदि रोजगार के सवाल पर चुनावी वर्ष में भी प्रदेश सरकार कुछ नया नही कर पायी तो भाजपा के लिए यह सबसे प्रभावी मुद्दों में से एक होगा।

हिमाचल की राजनीति में आरोपों का इतिहास लंबा है। सत्ता बदलती है, चार्जशीट बदलती है, आरोपी बदलते हैं और राजनीतिक बयान भी बदल जाते हैं। लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल वही रहता है कि किस मामले में आखिर हुआ क्या?

एफआईआर हुई तो जांच कहां पहुंची? जांच पूरी हुई तो चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं? चार्जशीट हुई तो अदालत में क्या हुआ? और यदि आरोप गलत निकले तो

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मरीज की मौत पर हिमकेयर फिर सवालों में

शिमला/शैल। पालमपुर में पैसों के अभाव और समय पर इलाज न मिलने से एक मरीज की मौत के मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुलह विधायक विपिन सिंह परमार ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मरीज को समय पर हिमकेयर योजना का लाभ मिलता और निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार उपलब्ध होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। परमार ने कहा, 'यह मृत्यु नहीं, सरकार द्वारा की गई हत्या है।'

शिमला में मीडिया से बातचीत में परमार ने कहा कि 50 हजार या डेढ़ लाख रुपये जैसी राशि के अभाव में किसी व्यक्ति की मौत होना सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण इन्हें प्रभावी रूप से बंद कर दिया।

परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में हाई-एंड सुविधाएं शुरू करने के दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर गरीब मरीजों को इलाज के लिए पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हिमकेयर का लाभ न मिलने से प्रदेश में अनेक परिवार परेशान हैं।

उन्होंने सरकार पर सरकारी रिकॉर्ड में जीवित लोगों को मृत घोषित किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया। परमार ने कहा कि यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हिमकेयर और सहारा योजनाओं को प्रभावी रूप से बहाल करने की मांग की।

परमार ने चेतावनी दी कि भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर हिमकेयर योजना पूरी प्रतिबद्धता के साथ फिर शुरू की जाएगी, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी जरूरतमंद की इलाज के अभाव में मौत न हो।

'विकसित भारत–2047' के लिए विश्वविद्यालयों को 100 दिन का रोडमैप, 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अब 'विकसित भारत–2047' के लक्ष्य को लेकर साझा रूप से काम करेंगे। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कविन्द्र गुप्ता ने लोक

भवन में कुलपतियों की बैठक के दौरान अंतर–विश्वविद्यालयीय 'विकसित भारत–2047' टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला को टास्क फोर्स का समन्वयक विश्वविद्यालय बनाया गया है।

राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को 10 दिनों के भीतर 100 दिवसीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें नवाचार, शोध, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और बेहतर कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित कार्यों का विवरण देना होगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों से अपनी सफल पहलों को दूसरे संस्थानों के साथ साझा करने को कहा, ताकि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसके लिए ज्ञान, नवाचार, कौशल, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों को मजबूत करना भी जरूरी है। उन्होंने टास्क फोर्स में विद्यार्थियों और उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

टास्क फोर्स की बैठक हर तीन महीने में होगी और इनका आयोजन अलग–अलग विश्वविद्यालयों में किया जाएगा। राज्यपाल ने कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण पौधशालाएं विकसित करने और किसानों को उन्नत बीज तथा औषधीय पौधे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से 'नशा मुक्त भारत अभियान' में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। खेल, फिटनेस, सांस्कृतिक गतिविधियों और परामर्श के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लोक भवन की पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया।

आईजीएमसी के शिशु वार्ड के लिए राज्यपाल ने रेडक्रॉस से भेंट किए 40 कंबल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आईजीएमसी शिमला के शिशु वार्ड के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से 40 कंबल भेंट किए। कंबल लोक

भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव और पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. कमल कांत शर्मा ने प्राप्त किए।

राज्यपाल ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता और मानव सेवा रेडक्रॉस आंदोलन की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचाराधीन बच्चों और उनके परिजनों के लिए छोटी–छोटी सहायता भी मुश्किल समय में बड़ा सहारा बन सकती है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर इलाज के साथ संवेदनशील और सहयोगी माहौल की भी जरूरत होती है। राज्यपाल ने मरीजों और उनके परिजनों तक सहायता पहुंचाने के लिए राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि आईजीएमसी प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाता है। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों और रेडक्रॉस सोसायटी के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, ताकि जरूरतमंद मरीजों को उपचार के साथ आवश्यक सहयोग भी मिल सके।

उन्होंने आपातकालीन और कठिन परिस्थितियों में मानवीय सहायता को और मजबूत करने की जरूरत बताई। साथ ही आम लोगों और संस्थाओं से मरीजों तथा जरूरतमंदों की मदद से जुड़ी गतिविधियों में आगे आने का आहवान किया।

राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस तरह की पहल से समाज में करुणा, संवेदनशीलता और सेवा की भावना मजबूत होगी और अधिक लोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज भी मौजूद रहे।

साइक्लिस्ट सोमेन देबनाथ ने राज्यपाल से की मुलाकात

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइक्लिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोमेन देबनाथ

ने लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने अपनी 19 वर्षों की साइकिल यात्रा के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी।

सोमेन देबनाथ ने बताया कि वह अब तक साइकिल से सात महाद्वीपों के 191 देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनके अभियान का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और मूल्यों का संदेश दुनिया तक पहुंचाना है।

उन्होंने अपने राष्ट्रव्यापी अभियान 'रीयूनियन भारत–वन ट्री, वन लाइफ, इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स' की भी जानकारी दी। इस अभियान के तहत वह देश के 28 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा कर रहे हैं। अभियान के दौरान राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण और खेलों को बढ़ावा देने का संदेश दिया जा रहा है।

राज्यपाल ने सोमेन देबनाथ के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यात्रा 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को खेल, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रसेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

राज्यपाल ने उनके अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की। सोमेन देबनाथ ने सहयोग के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन की बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रक्षा बन्धन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षा बन्धन का त्योहार समाज में आपसी भाई–चारे को बढ़ाने के साथ–साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पर्व भाई–बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी अवसर है।

उन्होंने कहा कि भाई–बहन के अटूट रिश्ते के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने रक्षा बंधन के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा।

राज्यपाल ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा–अर्चना, आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट पर जोर

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर जम्मू स्थित

प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति बालअइजी मंदिर में पूजा–अर्चना की। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की विशेष अभिषेक पूजा में हिस्सा लेकर देश में शांति, समृद्धि और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की।

राज्यपाल ने कहा कि रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा जैसे पर्व देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। ये त्योहार समाज में भाईचारे, सद्भाव और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं।

इस दौरान राज्यपाल ने जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मंदिर, धार्मिक स्थल और तीर्थस्थल हैं। इन स्थानों को बेहतर संपर्क सुविधाओं से जोड़कर और संयुक्त रूप से प्रचारित कर श्रद्धालुओं को बेहतर तीर्थयात्रा अनुभव दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जम्मू और हिमाचल की साझा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने भी प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

स्वस्थ युवा ही विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से नशे और शराब से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, जिम्मेदार और मजबूत युवा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कशियाना फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'नशामुक्त भारत एवं राष्ट्रीय नशामुक्ति सम्मान–2026' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज बनाने के लिए केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार और मजबूत पारिवारिक मूल्य दिए जाने चाहिए।

कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि परिवार और समाज की भूमिका नशे से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ों को खुद भी नशे से दूर रहकर बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

राज्यपाल ने नशामुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे कशियाना फाउंडेशन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने नशामुक्ति और सामाजिक कार्यों में बेहतर योगदान देने वाले विभिन्न संस्थानों और लोगों को राष्ट्रीय नशामुक्ति सम्मान–2026 प्रदान किए। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा नेता, पत्रकार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

अग्निवीर भर्ती बंद करने की मांग, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे सुक्खू

शिमला/शैल। भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर योजना को बंद कर सेना में नियमित भर्ती शुरू करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हिमाचल के पूर्व सैनिकों की भावनाओं से अवगत करवाएंगे।

बैठक में कुल्लू के पूर्व सैनिक शिवदयाल सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि चार साल की सेवा के बाद अधिकांश युवाओं को सेना से बाहर होना पड़ता है। इसके बाद उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलतीं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अग्निवीर योजना का सबसे अधिक असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जैसे सैनिक बहुल जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सेना में नियमित भर्ती के पक्ष में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेना में भर्ती कोटा कम होने से हिमाचल के युवाओं को निराशा हुई है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल ने देश को बड़ी संख्या में सैनिक दिए हैं और प्रदेश के जवानों ने देश की रक्षा में

महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि चार परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले हिमाचल के वीर जवानों की परंपरा को देखते हुए नियमित सेना भर्ती जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए भी प्रयास कर रही है। पुलिस विभाग में 1,300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की गई है और आने वाले समय में 1,000 और पद भरे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सरकार प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से भी प्राकृतिक खेती सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ने की अपील की।

सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल सैनिक बहुल प्रदेश है और पूर्व सैनिक राज्य की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स शुरू करने पर विचार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सरकारी संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता, भाईचारे और सद्भाव से ही आदर्श समाज का निर्माण संभव है। बैठक में विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 222 गौ सदनों और गौ अभयारण्यों में 23,018 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है। सात नए गौ सदनों का निर्माण पूरा होने के बाद 2,200 से 2,500 और पशुओं को आश्रय मिल सकेगा। गौवंश के पालन-पोषण के लिए सरकार 1,200 रुपये प्रति पशु प्रतिमाह सहायता दे रही है।

उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, डॉ. वाईएस परमार ऋण योजना, सीबीएसई विद्यालयों और रिवालसर के त्रिवेणी धाम की क्षतिग्रस्त चारदीवारी के पुनर्निर्माण सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।

डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय, कोटला सीएचसी होगा 24 घंटे संचालित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कार्यालय से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कस्बा कोटला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे संचालित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं डाडासीबा में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत 1,012 मछुआरा परिवारों को 35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने के बाद जनसभा में कीं। प्रत्येक परिवार के खाते में डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपये की राशि भेजी गई।

उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध की अवधि में मछुआरा परिवारों को यह सहायता दी जा रही है। सरकार ने मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' दो अक्तूबर से सोलन जिले से

शुरू करेगी। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना है।

उन्होंने 2023 की आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता 1.50 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख रुपये की गई है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर बद्दी में करीब 5,000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना काम शुरू किए आवंटित जमीन को रद्द करने पर विचार किया जा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाड़ी में 95 लाख रुपये से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन किया और डाडासीबा स्कूल के विज्ञान खंड सहित कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी।

पीएमएफएमई योजना में हिमाचल बना द्वितीय रनर-अप

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को मध्यम राज्य श्रेणी में द्वितीय रनर-अप का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से 24-25 अगस्त को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित पीएमएफएमई कॉन्क्लेव-2026 में प्रदान किया गया।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने यह पुरस्कार प्रदान किया। उद्योग विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक रमेश वर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे प्रदेश के लिए गौरव की उपलब्धि बताते हुए कहा कि पीएमएफएमई योजना से छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

प्रदेश में अब तक योजना के तहत 2,906 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल परियोजना लागत 191.73 करोड़ रुपये है, जबकि 73.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

योजना के तहत महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को भी लाभ मिला है। प्रदेश में करीब 16,083 एसएचजी सदस्यों को 59.29 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल सहायता प्रदान की गई है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान के लिए शिमला के जिला नोडल अधिकारी संजय कंवर को सर्वश्रेष्ठ जिला नोडल अधिकारी तथा जिला संसाधन व्यक्ति रविंद्र सिंह को सर्वश्रेष्ठ डीआरपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को तकनीकी सहायता देने के लिए पालमपुर, कुकुमसेरी और नौणी में तीन इनक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग ने योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है।

देहरा में भूमिगत डक्ट और बनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 100 करोड़:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा में शिमला की तर्ज पर भूमिगत यूटिलिटी

डक्ट बनाया जाएगा। बनखंडी में विकसित किए जा रहे जूलॉजिकल पार्क के लिए 100 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों और आम लोगों के हित में लगातार काम कर रही है।

देहरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देगी। 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बकाया, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बकाया वेतन के अलावा 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि श्रेणी-1, 2 और 3 के पेंशनरों के लिए बेसिक पे से जुड़ी शर्त हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद पात्र पेंशनरों को लंबित बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि' के तहत 800 मछुआरों को 3500-3500 रुपये की सहायता के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि मछली पर रॉयल्टी 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की गई है।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाया गया है और बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से जूलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 100 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कारवाई की बात कहते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त कर गरीबों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा।

देहरा अस्पताल में एक वर्ष के भीतर आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने और क्षेत्र में चल रही करीब 100 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने की भी बात कही।

एमबीए स्व-वित्तपोषित सीटों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में एमबीए (सामान्य) की स्व-वित्तपोषित सीटों पर प्रवेश के लिए 3 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सुबह 10 बजे से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में आयोजित किया जाएगा। कक्षाएं 10 सितंबर से शुरू होंगी।

प्रवेश के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत छूट निर्धारित है। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट में दसवीं के अंकों को 40 प्रतिशत, जमा दो को 30 प्रतिशत और स्नातक के अंकों को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज, स्व-सत्यापित प्रतियां और 2,200 रुपये शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट साथ लाना होगा। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uhf.ac.in पर उपलब्ध है।

मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

प्रकृति की सीमा लांघकर विकास नहीं हो सकता

हिमालय इस समय केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि बदलते जलवायु संकट और बढ़ते आपदा जोखिम की चेतावनी भी है। नेपाल में 26 अगस्त को ग्लेशियर और चट्टानों के ढहने से पैदा हुई भयावह बाढ़ ने जिस तरह कुछ ही समय में बस्तियों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को तबाह किया, उसने पूरे हिमालयी क्षेत्र को झकझोर दिया है। शुरुआती आकलनों में सैकड़ों मौतें और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई हैं। यह घटना हिमाचल प्रदेश के लिए महज पड़ोसी देश की त्रासदी नहीं है। यह हमारे सामने खड़ा हुआ एक सीधा सवाल है – क्या हमने अपनी पिछली आपदाओं से पर्याप्त सबक लिया है?

नेपाल की घटना की सबसे गंभीर बात इसकी अचानकता है। ग्लेशियर टूटने, बर्फ और चट्टानों के मलबे के नदी में गिरने और उसके बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का अवसर तक नहीं दिया। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय के तेजी से गर्म होते वातावरण में ग्लेशियरों की अस्थिरता बढ़ रही है और ऐसी घटनाओं का खतरा गंभीर होता जा रहा है। हिमाचल भी इसी संवेदनशील हिमालयी पट्टी का हिस्सा है। इसलिए यह मान लेना कि ऐसी आपदा केवल नेपाल तक सीमित रह सकती है, आत्मघाती लापरवाही होगी।

हिमाचल ने पिछले वर्षों में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से होने वाली तबाही देखी है। मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला और सिरमौर सहित कई क्षेत्रों में सड़कें, पुल, मकान और बिजली परियोजनाएं प्रभावित होती रही हैं। हर बड़ी आपदा के बाद राहत और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं, समितियां बनती हैं और कुछ समय बाद सामान्य जीवन लौट आता है। लेकिन मूल प्रश्न वहीं खड़ा रहता है – आपदा आने से पहले हमारी तैयारी कितनी मजबूत है?

आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल राहत सामग्री और बचाव दल तैयार रखना नहीं है। असली आपदा प्रबंधन खतरे की पहचान से शुरू होता है। जहां खतरा हो, वहां समय रहते चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यावरण और जमीन से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं के वैज्ञानिक आकलन को विकास परियोजनाओं की औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य शर्त बनाया जाये। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जलविद्युत का बड़ा महत्व है, लेकिन नदी घाटियों में बढ़ता निर्माण और सड़क कटिंग पहाड़ी पारिस्थितिकी पर दबाव डालते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विकास की सीमा प्रकृति की वहन क्षमता से तय हो, न कि परियोजनाओं की आर्थिक महत्वाकांक्षा से।

यदि स्थानीय लोगों को प्राथमिक बचाव, संचार, सुरक्षित स्थानों और आपातकालीन निकासी की जानकारी हो तो शुरुआती घंटों में अनेक जानें बचाई जा सकती हैं। हर संवेदनशील पंचायत में स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया दल, आवश्यक उपकरण और स्पष्ट निकासी योजना होनी चाहिए। हिमाचल जैसे राज्य में विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल केवल परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

प्रकृति को चुनौती देकर विकास की रफ्तार बढ़ाने की कीमत अंततः समाज को चुकानी पड़ती है। हिमालय न तो असीमित सड़कें चाहता है, न असीमित निर्माण और न ही बिना वैज्ञानिक अध्ययन के हर घाटी में परियोजनाएं। हमें विकास और पर्यावरण के बीच चुनाव नहीं, बल्कि दोनों के बीच संतुलन की ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें मानव जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

नेपाल की त्रासदी पर दुख जताना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हिमाचल ने इससे केवल संवेदना जताने का काम किया और अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया तो यह त्रासदी हमारे लिए केवल एक खबर बनकर रह जाएगी। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगली आपदा आने से पहले हम वह सब कर लें, जो आपदा के बाद करने के लिए मजबूर न होना पड़े। हिमाचल को अब राहत आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर पूर्व चेतावनी, जोखिम आधारित नियोजन और प्रकृति के अनुरूप विकास का मॉडल अपनाना होगा। क्योंकि हिमालय चेतावनी दे रहा है – और इस चेतावनी को अनसुना करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।

क्या वामपंथ फिर लौट रहा है?
रामलीला मैदान की CPI रैली और बदलते जनमिजाज का संकेत

गौतम चौधरी

आज दिल्ली का रामलीला मैदान केवल एक राजनीतिक सभा का साक्षी नहीं होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 'बदलाव जरूरी है' रैली को यदि अपेक्षित जनसमर्थन मिलता है, तो इसे भारतीय राजनीति के उस अध्याय की वापसी का संकेत भी माना जा सकता है, जिसे पिछले कुछ दशकों में लगभग अप्रासंगिक मान लिया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI कभी देश की राजनीति की केंद्रीय धुरी हुआ करती थी। आज उसकी लोकसभा में उपस्थिति सीमित है और चुनावी प्रभाव भी पहले जैसा नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में CPI को लगभग 0.49 प्रतिशत मत और दो सीटें मिलीं। इसलिए सामान्य चुनावी गणित के आधार पर CPI को राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी ताकत मानने का कोई आधार नहीं है लेकिन राजनीति केवल चुनावी सीटों और वोट प्रतिशत से नहीं चलती। कई बार राजनीतिक विचार चुनावी पराजय के बावजूद समाज में जीवित रहते हैं और परिस्थितियां बदलते ही फिर प्रासंगिक हो जाते हैं। रामलीला मैदान की आज की रैली को इसी संदर्भ में देखना चाहिए।

CPI ने इस रैली को अचानक आयोजित नहीं किया है। इसके पहले 6 से 15 अगस्त तक देश के विभिन्न हिस्सों में पदयात्राएं और जनसंपर्क अभियान चलाए गए। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, श्रमिक अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा जैसे सवालों को लेकर पार्टी ने गांवों और कस्बों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। यही इस पूरे अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात है।

आज CPI जिस मुद्दे को उठा रही है, वे किसी एक राजनीतिक दल के मुद्दे नहीं हैं। महंगाई हर परिवार का सवाल है। रोजगार हर युवा का सवाल है। किसानों की आय और फसल का उचित मूल्य ग्रामीण भारत का सवाल है। सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी की आवश्यकता है। यानी CPI उन सवालों को राजनीतिक एजेंडे पर ला रही है, जिनका संबंध सीधे नागरिक के जीवन से है। यहां मोदी सरकार की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत ने तेज आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वैश्विक स्तर पर अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन विकास की इस चमक के समानांतर बेरोजगारी, आय में असमानता, ग्रामीण संकट और परिवारों की वास्तविक क्रयशक्ति जैसे सवाल भी लगातार बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और असमानता महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों के रूप में सामने आए थे। यही वह जगह है जहां वामपंथ को अपनी पुरानी जमीन फिर दिखाई दे सकती है।

फिलहाल यह निष्कर्ष निकालना भूल होगी कि मोदी सरकार की कथित विफलताओं से स्वतः CPI मजबूत हो जाएगी। भारतीय राजनीति में सत्ता से असंतोष का लाभ हमेशा वामपंथ को नहीं मिलता। उसका लाभ कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों अथवा दूसरे विपक्षी दलों को भी मिल सकता है। इसलिए CPI के सामने चुनौती केवल मोदी सरकार की आलोचना करने की नहीं है। चुनौती यह है कि वह लोगों को यह विश्वास दिलाए कि उसके पास वर्तमान आर्थिक और सामाजिक संकट का वैकल्पिक रास्ता भी है। 'बदलाव जरूरी है' का नारा तभी राजनीतिक अर्थ ग्रहण करेगा, जब उसके साथ यह स्पष्ट हो कि बदलाव कैसा और किसके लिए? यहीं डी. राजा के नेतृत्व की परीक्षा है।

CPI महासचिव डी. राजा ने इस अभियान को केवल दिल्ली की एक रैली तक सीमित नहीं रखा है। उनका प्रयास है कि पार्टी को फिर से जनसंघर्षों के बीच ले जाया जाए। रोजगार, महंगाई, किसान, मजदूर, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों को एक साझा राजनीतिक विमर्श में जोड़ने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा है।

यदि कल रामलीला मैदान में बड़ी भीड़ जुटती है, तो उसका श्रेय केवल डी. राजा को देना भी उचित नहीं होगा। CPI के पास दशकों पुराना कैडर नेटवर्क है। मजदूर संगठनों, किसान संगठनों, छात्र-युवा संगठनों और स्थानीय पार्टी इकाइयों का नेटवर्क आज भी मौजूद है।

फिर भी इस बात को कम करके नहीं आंका जा सकता कि इतने सीमित चुनावी संसाधनों वाली पार्टी यदि देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों को दिल्ली तक लामबंद कर पाती है, तो यह उसके संगठनात्मक पुनर्जीवन का संकेत होगा।

और यदि यह लामबंदी केवल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित न रहकर आम नागरिकों को भी आकर्षित करती है, तब इसका राजनीतिक महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा।

राजनीतिक रैलियों में भीड़ का अपना आकर्षण होता है। लेकिन लोकतंत्र में भीड़ ही जनसमर्थन का अंतिम प्रमाण नहीं है। एक लाख लोग रामलीला मैदान में आ जाएं, इससे CPI अगले चुनाव में एक लाख नए वोट पा जाएगी – ऐसा कोई सीधा गणित नहीं है लेकिन यदि सीमित आर्थिक संसाधनों वाली एक पुरानी वामपंथी पार्टी अपने आहवान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दिल्ली ला पाती है, तो एक दूसरा प्रश्न जरूर उठेगा – लोग आए क्यों? क्या वे केवल पार्टी कार्यकर्ता हैं, क्या वे महंगाई और बेरोजगारी से परेशान नागरिक हैं, क्या किसान और मजदूर अपने पुराने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तलाश में हैं, क्या युवा उस आर्थिक व्यवस्था से निराश हैं, जिसमें विकास के आंकड़े तो तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार का सवाल अनुत्तरित रहता है? यही प्रश्न इस रैली को महज राजनीतिक आयोजन से आगे ले जाएगा।

CPI के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है। यदि पार्टी केवल मोदी विरोध को अपनी राजनीति का आधार बनाती है, तो वह विपक्ष की अनेक पार्टियों में से एक बनकर रह जाएगी। यदि वह महंगाई और बेरोजगारी को वर्गीय प्रश्नों से जोड़ते हुए यह समझाने में सफल होती है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहा, सार्वजनिक संस्थाएं क्यों कमजोर हो रही हैं, किसानों और श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति क्यों घट रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है – तो वामपंथ की राजनीति को एक नई वैचारिक जमीन मिल सकती है। यही CPI की वास्तविक संभावना है।

वस्तुतः आज देश में वामपंथ के लिए परिस्थितियां paradoxical हैं। चुनावी ताकत पहले जैसी नहीं है, लेकिन जिन आर्थिक और सामाजिक सवालों को वह दशकों से उठाता रहा है, वे खत्म भी नहीं हुए हैं। बल्कि अनेक मामलों में वे और जटिल हुए हैं।

CPI की 'बदलाव जरूरी है' रैली को न तो एक दिन में वामपंथ की वापसी घोषित करना चाहिए और न ही उसे सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन मानकर खारिज करना चाहिए। कल की भीड़ यदि बड़ी होती है, तो यह CPI के संगठन की ताकत का संकेत होगी। यदि उस भीड़ में बड़ी संख्या आम नागरिकों की दिखाई देती है, तो यह जनमिजाज में परिवर्तन का संकेत हो सकता है।

यदि इस रैली के बाद CPI देश के गांवों, कारखानों, खेतों, विश्वविद्यालयों और मजदूर बस्तियों में अपने आंदोलन को लगातार विस्तार देती है, तब यह कहना उचित होगा कि भारतीय वामपंथ केवल अतीत की स्मृति नहीं रह गया है। यहां मोदी सरकार के लिए भी एक राजनीतिक संदेश छिपा है।

किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की कमजोरी अंततः सत्ता के लिए भी स्वस्थ स्थिति नहीं होती। मजबूत विपक्ष सत्ता को जवाबदेह बनाता है। और यदि आर्थिक असंतोष, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे सवालों पर मुख्यधारा के विपक्ष के साथ-साथ वामपंथ भी अपनी जमीन बनाने लगता है, तो राष्ट्रीय राजनीति का विमर्श बदल सकता है। रामलीला मैदान कल शायद केवल CPI की ताकत नहीं बताएगा।

वह यह भी बताएगा कि भारत का आम नागरिक किस तरह की राजनीति सुनना चाहता है – सिर्फ उपलब्धियों की राजनीति या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों की राजनीति। शायद इसी अर्थ में CPI का 'बदलाव जरूरी है' नारा सबसे पहले स्वयं CPI के लिए भी है। उसे अपने अतीत की विरासत से बाहर निकलकर वर्तमान भारत के नए श्रमिक, नए किसान, नए युवा और नए मध्यवर्ग से संवाद करना होगा। यदि वह ऐसा कर पाती है, तो कल की रैली केवल एक भीड़ नहीं होगी। वह भारतीय राजनीति में एक भूले हुए विचार के पुनः दस्तक देने की आवाज हो सकती है।

'हर काम देश के नाम'

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा हुए सेवानिवृत्त – राष्ट्र सेवा के एक शताब्दी – दीर्घ पारिवारिक गौरव का अध्याय हुआ पूर्ण।

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग – इन – चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC), आज 31 अगस्त 2026 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। इसके साथ ही राष्ट्र के प्रति उनकी 39 वर्षों की गौरवपूर्ण एवं समर्पित सैन्य सेवा का अध्याय पूर्ण हुआ।

दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ऐसे गौरवशाली परिवार से आते हैं, जिसने सामूहिक रूप से एक शताब्दी से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा की है। उनके पिता स्वर्गीय विंग कमांडर शिव कुमार शर्मा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट थे और उन्होंने चार सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया – 1961 में गोवा, 1962 में फुकचेह एवं डेमचोक, 1965 में हलवारा तथा 1971 में पठानकोट। वर्ष 1965 में सर्गोधा के ऊपर उनका विमान मार गिराया गया, जिसमें उन्होंने रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बावजूद इजेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने पुन: स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर 1971 तक लड़ाकू विमान उड़ाने की क्षमता हासिल कर ली। उनके ससुर ब्रिगेडियर सरजीत सिंह कालेर (सेवानिवृत्त) ने तीनों प्रमुख युद्धों में भाग लिया – 1962 में रेजांगला, 1965 में 1 जाट लाइट इन्फैंट्री के साथ अमृतसर – लाहौर सेक्टर में तथा 1971 में 1 जाट के एडजुटेंट के रूप में। बाद में उन्होंने 2 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री (1 JAT) की कमान भी संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा के बड़े भाई एयर कमोडोर शैलेंद्र शर्मा, वायु सेना मेडल (सेवानिवृत्त), मिराज – 2000 पायलट रहे हैं और उन्होंने 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल, द्रास एवं मश्कोह क्षेत्रों में हवाई हमलों में भाग लिया।

मेयो कॉलेज, अजमेर के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने अपने सैन्य जीवन के प्रारंभिक चरण में ही असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (71वां कोर्स) में वे अकादमी कैडेट कैप्टन रहे। भारतीय सैन्य अकादमी (81 रेगुलर कोर्स) में भी वे अकादमी अंडर ऑफिसर रहे तथा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और सिख लाइट इन्फैंट्री मेडल फॉर बेस्ट स्पोर्ट्समैन से सम्मानित हुए। इस प्रकार वे अपने कोर्स के सर्वश्रेष्ठ कैडेट तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, दोनों का गौरव प्राप्त करने वाले दुर्लभ अधिकारियों में शामिल रहे। उन्होंने 19 दिसंबर 1987 को भारतीय सेना की पुरानी एवं गौरवशाली बख्तरबंद रेजिमेंट 'The Scinde Horse' में कमीशन प्राप्त किया।

अपने सैन्य जीवन के प्रारंभिक वर्षों में 11 राजपूताना राइफल्स के साथ जम्मू – कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवाद – रोधी अभियानों में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल (वीरता) से अलंकृत किया गया। आगे चलकर उन्होने The Scinde Horse, एक आर्मर्ड ब्रिगेड, एक इन्फैंट्री डिवीजन तथा एक पिवट कोर की कमान संभाली ये सभी नियुक्तियां पश्चिमी मोर्चे पर महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने स्ट्राइक कोर के बीजीएस (ऑपरेशंस), मेजर जनरल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस) तथा कमांड मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ सहित कई महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर भी कार्य किया। उन्हें दो बार विदेश में सेवा का अवसर मिला। पहली बार उन्होंने भूटान स्थित मुख्यालय इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम में जीएसओ – 2 (ऑपरेशंस) के रूप में सेवा दी तथा बाद में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (MONUSCO) में चीफ मिलिट्री पर्सनल ऑफिसर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने 52 देशों के 21,000 से अधिक सैनिकों के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली।

डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन तथा इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में समग्र मेरिट क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त कर 'चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रॉफी' हासिल की। वर्ष 2024 में मेयो कॉलेज, अजमेर द्वारा उन्हें व्यावसायिक उत्कृष्टता एवं प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए जेटीएम गिब्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 01 जुलाई 2024 को आर्मी ट्रेनिंग कमांड के 25वें आर्मी कमांडर के रूप में कमान संभाली।

आर्मी ट्रेनिंग कमांड में परिवर्तनकारी कार्यकाल।

आर्मी ट्रेनिंग कमांड में उनका कार्यकाल कमांड के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी कार्यकालों में से एक रहा। उनके नेतृत्व मे ARTRAC ने चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ क्वाड्रेनियल ट्रेनिंग डायरेक्टिव 2025 – 2029 (COAS Quadrennial Training Directive) जारी किया तथा ड्रोन वारफेयर प्रशिक्षण को अग्रणी रूप से संस्थागत बनाया। इसके अंतर्गत 50,000 से अधिक सैन्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और मानव रहित प्रणालियों से संबंधित क्षमता को एक सीमित विशेषज्ञता से आगे बढ़ाकर एक बुनियादी सैन्य दक्षता के रूप में विकसित किया गया।

उनके कार्यकाल में मैन्युवर वारफेयर रेंज, अर्बन वारफेयर नोड्स तथा साइबर एवं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज स्थापित करने की पहल की गई। साथ ही, 'विदुर वक्ता' (कॉग्निटिव रेड टीमिंग) को पूरे भारतीय सेना में अपनाने के लिए संस्थागत रूप दिया गया। उनके नेतृत्व में ARTRAC ने 74 प्रकाशन, पांच महत्वपूर्ण सैन्य सिद्धांत (डॉक्ट्रिन), प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ 40 समझौता ज्ञापन (MoUs) और 33 सेमिनार आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, 15 प्रतिष्ठानों को सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज के रूप में विकसित किया गया, ताकि वर्ष 2030 तक 33 नई एवं विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को

आत्मसात किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश एवं शिमला में योगदान।

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा के कार्यकाल का हिमाचल प्रदेश और शिमला पर भी उल्लेखनीय प्रभाव रहा। 23 मार्च 2026 को मुख्यालय ARTRAC ने अन्नाडेल में 'श्रद्धांजलि स्थल' राष्ट्र को समर्पित किया। यह राज्य की राजधानी में युद्ध वीरों की स्मृति में स्थापित पहला और एकमात्र ऐसा स्मारक है, जिसके शीर्ष पर 52 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित है। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण किया गया, जो हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक रेटिंग वाले संग्रहालयों में उभरा। इसमें नई अन्नाडेल गैलरी तथा एआर – वीआर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किए गए। 13,675 सदस्यीय पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण के लिए शिमला सीएसडी कैंटीन का जीर्णोद्धार, हमीरपुर सीएसडी कैंटीन का स्थानांतरण तथा शिमला ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला में स्थानांतरित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सैन्य एवं नागरिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए आर्मी डे रन, कारगिल विजय दिवस समारोह का गैटी थिएटर में आयोजन, पूर्व सैनिकों को 'योद्धा सम्मान' के तहत नकद पुरस्कार तथा राज्य पुलिसकर्मियों सहित दस नागरिकों को जीओसी – इन – सी कमेंडेशन प्रदान किए गए।

उनके कार्यकाल के दौरान लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026, भविष्य के लिए भारतीय सेना को तैयार करने हेतु इंडियन आर्मी फ्यूचर्स ट्रेनिंग कमांड IAFTC की परिकल्पना, नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने तथा योग्यता एवं मेरिट की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए व्यापक एग्जाम सेल सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी आगे बढ़ाए गए।

28 अगस्त 2026 को आर्मी कमांडर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आर्मी ट्रेनिंग कमांड के सभी अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने एआरटीआरएसी को बहु – क्षेत्रीय युद्धक तैयारी के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में परिवर्तित करने तथा 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। विश्वभर में बदलते संघर्षों तथा पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर उभरते खतरों के संदर्भ में उन्होंने पूर्ण – स्पेक्ट्रम युद्धक तैयारी, तीव्र गति से प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने तथा सशक्त, सक्षम, लचीले और चुस्त कनिष्ठ नेतृत्व पर बल दिया। उन्होंने 'प्रक्रिया – उन्मुखता' से 'परिणाम एवं क्षमता – उन्मुखता' की ओर संस्थागत बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए इंडियन आर्मी फ्यूचर्स ट्रेनिंग कमांड IAFTC की स्थापना की पुरजोर वकालत की। इसका उद्देश्य एक सक्रिय, अनुकूलनशील और प्रौद्योगिकी – सक्षम सेना का निर्माण करना है। उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक संस्थागत प्रयास के केंद्र में सैनिक ही होना चाहिए। उन्होंने सभी रैंकों का आहवान किया कि वे 'शून्य – त्रुटि मानसिकता' से बाहर निकलें, समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा दें तथा भविष्य की सैन्य प्रशिक्षण व्यवस्था और परिचालन तैयारियों के लिए उच्च मानदंड स्थापित करते रहें।

'The Scinde Horse' के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल ।

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा अपनी रेजिमेंट 'The Scinde Horse' के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल एवं आर्मी कमांडर हैं तथा इस रेजिमेंट के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारी भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान उन्हें भारतीय सेना की 12 गौरवशाली आर्मर्ड रेजिमेंटों का कर्नल नियुक्त किया गया। इनमें 4 हॉर्स (हॉडसन हॉर्स), 14 हॉर्स (The Scinde Horse), 20 लांसर्स, 42 आर्मर्ड रेजिमेंट, 46 आर्मर्ड रेजिमेंट, 54 आर्मर्ड रेजिमेंट, 63 कैवेलरी, 67 आर्मर्ड रेजिमेंट, 70 आर्मर्ड रेजिमेंट, 81 आर्मर्ड रेजिमेंट, 84 आर्मर्ड रेजिमेंट और 88 आर्मर्ड रेजिमेंट शामिल हैं। सेवानिवृत्ति के साथ वे इन सभी प्रतिष्ठित रेजिमेंटों की कर्नलशिप से मुक्त हो रहे हैं, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं गार्ड ऑफ ऑनर ।

31 अगस्त 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने अन्नाडेल स्थित 'श्रद्धांजलि स्थल' पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके पश्चात अन्नाडेल में 111 इन्फैंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी (कुमाऊं) की सम्मान गार्ड द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

एक उत्कृष्ट पेशेवर और एक समर्पित सैनिक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा भारतीय सेना से दूरदर्शी नेतृत्व, संस्थागत सुधार और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की अमिट विरासत छोड़कर सेवानिवृत हुए।

ग्रामीण बैंकों का कारोबार 13.5 लाख करोड़ रूपये के पार

शिमला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने वित्त वर्ष 2025 – 26 में बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 28 आरआरबी का कुल कारोबार 13.5 लाख करोड़ रूपये के पार पहुंच गया है। वहीं, इन बैंकों का कुल शुद्ध मुनाफा बढ़कर 10,176 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024 – 25 में आरआरबी का कुल मुनाफा 6,820 करोड़ रूपये था।

आरआरबी की वित्तीय स्थिति में सुधार का असर खराब कर्ज के आंकड़ों पर भी दिखाई दिया है। वित्त वर्ष 2025 – 26 में सकल गैर – निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) घटकर 5.3 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 2.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर हैं। इससे आरआरबी की ऋण वसूली और वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत मिलता है।

वर्तमान में 28 आरआरबी 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 700 जिलों में 22,273 शाखाओं के जरिए बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में इन बैंकों की अहम भूमिका है।

वित्तीय समावेशन के तहत आरआरबी ने वित्त वर्ष 2025 – 26 में 54.98 लाख से अधिक नए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले। जनधन खातों के माध्यम से उन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है जो लंबे समय तक औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रहे। इन खातों के जरिए सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने और ग्रामीण आबादी को बचत, बीमा, पेंशन तथा अन्य वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था को मजबूती मिलती है।आरआरबी का क्रेडिट – डिपॉजिट अनुपात भी बढ़कर 75.2 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि बैंकों में जमा राशि का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में लोगों और कारोबार तक पहुंच रहा है।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने आरआरबी को डिजिटल बैंकिंग बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। प्रायोजक बैंकों से आरआरबी के आईटी ढांचे को मजबूत करने में सहयोग करने को कहा गया है।

देहरा में 46 करोड़ से बनेगी प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल परियोजना:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 46 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। भविष्य में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बब्ल थोर में जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने से कई बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बब्ल थोर में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायत स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार

कई कदम उठा रही है। युवाओं और महिला मंडलों को पौधरोपण तथा वन संरक्षण से जोड़ने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। पौधों के जीवित रहने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने चनौर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ से लगेंगी आधुनिक मशीनें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस राशि से अत्याधुनिक डायग्नॉस्टिक मशीनें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कई मशीनें अभी केवल दिल्ली

के एम्स में उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में जन स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नई मशीनों के आने से मरीजों की जांच अधिक सटीक होगी और उन्हें समय पर सही उपचार मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के 70 आदर्श चिकित्सा संस्थानों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है। सरकार 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर्ती करने जा रही है। नादौन, कांगू, गलोड़ और धनेटा के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जोल सप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किया जाएगा। यहां उत्तर भारत का पहला अलाइड हेल्थ सर्विसेज संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसी सत्र से यहां दाखिले शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिए गए हैं। इससे अलाइड हेल्थ सर्विसेज से जुड़े प्रशिक्षित प्रोफेशनल हमीरपुर में ही तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री ने लोगों से जन स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नादौन और हमीरपुर के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि कांगू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का दर्जा दिया गया है। यहां नया भवन बनाया जाएगा और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा सहित जरूरी क्षेत्रों के लिए बजट की कमी नहीं रहने दी जा रही है।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नादौन में 17.52 करोड़ से बनेगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नया भवन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नादौन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) के नए भवन की आधारशिला रखी। भवन के निर्माण पर 17.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भवन का निर्माण इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए स्कूल भवन में छह कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, दो स्टाफ रूम, प्रधानाचार्य कार्यालय, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, एनएसएस कक्ष के साथ संगीत, नृत्य और कला कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक भवन बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 30 सितंबर तक अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर की जा रही है।

उन्होंने बताया कि नादौन में अत्याधुनिक खेल परिसर भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें करीब 14

इनडोर खेलों की सुविधाएं होंगी। इससे युवाओं को खेल सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्र में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में एम्स स्तर के आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना के लिए करीब 74 बीघा जमीन चिन्हित की गई है और निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जिले में एलाइड एंड हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

उन्होंने नादौन पुल के पास ब्यास नदी किनारे करीब 250 करोड़ रुपये से नया घाट विकसित करने और बस स्टैंड के स्तरोन्नयन की बात भी कही।

एचपी शिवा परियोजना में मंडी सबसे आगे, 993 हेक्टेयर में पौधरोपण पूरा

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के तहत पौधरोपण और

खेत तैयार करने के कार्यों की समीक्षा की। एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषित यह परियोजना प्रदेश के सात जिलों में चल रही है।

बैठक में बताया गया कि मंडी जिले में करीब 993 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण पूरा हो चुका है, जो सातों जिलों में सबसे अधिक है। परियोजना के तहत मार्च 2027 तक 3,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 2,600 हेक्टेयर भूमि पौधरोपण के लिए तैयार की जा चुकी है।

मंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने और पौधरोपण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में परियोजना के तहत करीब 9 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि मौजूदा सीजन में सितंबर तक करीब 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।

समीक्षा के दौरान कुछ क्लस्टरों में नर्सरियों से भेजे गए पौधे निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरे नहीं पाए गए। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल तय गुणवत्ता वाले पौधे ही लगाए जाएं।

उन्होंने नर्सरी संचालकों को भी गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उप-निदेशकों को पौधों की आपूर्ति के समय नर्सरी में अधिकारी तैनात करने को कहा गया, जो पौधों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच करेंगे। मंत्री ने धरातल पर निगरानी बढ़ाने और पौधरोपण के साथ संबंधित ढांचागत कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में समर्थ अत्री का शानदार प्रदर्शन

शिमला/शैल। देहरादून में 17 से 20 अगस्त तक आयोजित एशियन

ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी-2026 में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी समर्थ अत्री ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

ऑकलैंड हाउस स्कूल के कक्षा 10 के छात्र समर्थ अत्री ने जूनियर-बी पुरुष वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशिया में 22वां स्थान हासिल किया।

समर्थ ने 1500 मीटर स्पर्धा में 2 मिनट 51 सेकेंड का समय दर्ज किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस स्पर्धा में उन्होंने एशिया में 21वां स्थान हासिल किया। वहीं, 1000 मीटर दौड़ में 1 मिनट 49 सेकेंड का समय निकालकर एशिया में 27वां स्थान प्राप्त किया।

500 मीटर स्पर्धा में भी समर्थ ने प्रभावी प्रदर्शन किया और एशिया में 16वां स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे।

प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के करीब 11 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था। इनमें ऑकलैंड हाउस स्कूल के दो विद्यार्थी शामिल थे।

समर्थ की इस उपलब्धि को स्कूल और हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के बीच प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिचय दिया। उनकी उपलब्धि से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम हटेगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के दाखिला फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करना और बच्चों में समानता तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर से ही जाति की पहचान को अलग रखने की शुरुआत की जाएगी, ताकि बच्चों में किसी तरह की हीन भावना पैदा न हो।

हालांकि, सरकारी योजनाओं और आरक्षण सहित अन्य आवश्यक लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को जाति संबंधी जानकारी देने की सुविधा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के तहत परियोजनाओं के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 4 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति के कारण किसी विद्यार्थी को पढ़ाई बीच में छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अति निर्धन परिवारों के लिए प्रस्तावित 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना का भी उल्लेख किया। इसके तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और परिवार की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 1,400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

राज्यपाल ने चिराग भानु सिंह को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई

भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल ने अतिरिक्त न्यायाधीश पद की शपथ ली

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोकभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह के दौरान चिराग भानु सिंह को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया भी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल को उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया व भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट को पढ़ा, जिसके तहत चिराग भानु सिंह को

राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने राज्यपाल व नव-नियुक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों के शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

वाहनों की आयु सीमा तय करने का अधिकार केंद्र के पास, 15 साल करने की मांग उठाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में वाहनों की आयु सीमा को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मोटर

वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 के तहत वाहनों की आयु सीमा तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार अपने स्तर पर इसमें बदलाव नहीं कर सकती।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। सरकार ने केंद्र से इस संबंध में आवश्यक कारवाई का अनुरोध किया है।

केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के तहत आने वाले वाहनों की आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कांट्रैक्ट कैरिज वाहनों के लिए भी यही सीमा लागू होनी चाहिए।

जब तक केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं लेती, इच्छुक ऑपरेटर नियमों के तहत एआईटीपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से अब तक 1,009 ऑपरेटर एआईटीपी पोर्टल का लाभ उठा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्वचालित परीक्षण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में बद्दी, हरोली और नादौन में तीन केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जबकि निजी क्षेत्र में कांगड़ा के रानीताल, मंडी के कांगू, बिलासपुर, नालागढ़ और पांवटा साहिब में पांच केंद्र स्वीकृत हैं।

रानीताल और कांगू के निजी केंद्र शुरू हो चुके हैं, जबकि अन्य केंद्रों पर काम चल रहा है। इसके अलावा जसूर/डमटाल, पालमपुर, काला अंब, भुंतर और बनीखेत में पांच और केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

कांगड़ा में पुरानी पद्धति से फिटनेस जांच जारी रखने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 'थेरेपी ऑन व्हील्स' शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 'मोबाइल रिसोर्स सेंटर-थेरेपी ऑन व्हील्स' के तहत तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सुविधा प्रारंभिक चरण में मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में उपलब्ध होगी।

समग्र शिक्षा और सैम्फिया फाउंडेशन के सहयोग से चलने वाली इस पहल के तहत बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एवं लैंग्वेज थेरेपी, विशेष शिक्षा, स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और पुनर्वास सेवाएं मिलेंगी। अभिभावकों को परामर्श और बच्चों की जरूरत के अनुसार फॉलो-अप तथा रेफरल सुविधा भी दी जाएगी।

इस पहल का खास लाभ ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगा, जहां विशेष सेवाओं तक पहुंच सीमित है। बच्चों की समय पर पहचान और स्क्रीनिंग के साथ शिक्षकों व अभिभावकों को प्रशिक्षण और जागरूकता भी दी जाएगी। सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से इस सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों तक करने की है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, संचार कौशल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

वन महोत्सव के साथ नेरी महाविद्यालय ने मनाया स्थापना दिवस

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी ने वन महोत्सव-2026

के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन नेरी स्थित फॉरेस्ट्री फार्म, खग्गल में किया गया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सतीश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने महाविद्यालय की प्रगति में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से महाविद्यालय औद्यानिकी एवं वानिकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना है।

वन महोत्सव के तहत फॉरेस्ट्री फार्म में तूनी, मालाबार नीम, अर्जुन, लसौड़ा, हरड़, आंवला और सहजन सहित करीब 120 पौधे लगाए गए। पौधरोपण में करीब 100 शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

फल विज्ञान विभाग की ओर से एवोकाडो पौधरोपण अभियान भी चलाया गया। इसमें एवोकाडो की विभिन्न किस्मों के करीब 40 पौधे लगाए गए। डॉ. शर्मा ने विद्यार्थियों से अपने लगाए पौधों की जिम्मेदारी लेने और उनकी नियमित देखभाल करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को बागवानी प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा।

महाविद्यालय की शुरुआत 29 अक्तूबर 1999 को क्षेत्रीय औद्यानिकी एवं वानिकी अनुसंधान केंद्र, भोटा से हुई थी। 2014 में इसे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नेरी के रूप में विकसित किया गया।

वर्तमान में यहां हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के स्नातक पाठयक्रमों के साथ 15 विषयों में एमएससी और सात विषयों में पीएचडी कार्यक्रम संचालित हैं। स्थापना के बाद से अब तक 639 स्नातक, 34 स्नातकोत्तर और पांच पीएचडी शोधार्थी अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं।

पंचायत चौकीदारों की मांगों पर सरकार संवेदनशील:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायत चौकीदारों की लंबित मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 9 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों के हित में काम कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी के साथ गाय और भैंस के दूध के लिए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस देना सरकार का सामाजिक फैसला है। साथ ही दावा किया कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

राहुल गांधी पर FIR के विरोध में शिमला में कांग्रेस का प्रदर्शन

शिमला/शैल। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने शिमला में प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एफआईआर को राजनीतिक बदले की कारवाई बताया और कहा कि राहुल गांधी ने केवल एक गंभीर सामाजिक मुद्दा उठाया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और एफआईआर वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की सभा के बाद कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल के 'शुद्धिकरण' का मामला सामने आया था। कांग्रेस ने इसे दलित समाज के अपमान से जोड़ा। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया था कि किसी दलित नेता की सभा के बाद इस तरह की कारवाई क्यों की गई और जिम्मेदार लोगों पर कारवाई क्यों नहीं हो रही है।

इसके बाद हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने सफाई की सामान्य प्रक्रिया को जातीय भेदभाव से जोड़कर वाल्मीकि समाज का अपमान किया और समाज में गलत संदेश दिया।

एफआईआर के विरोध में शिमला में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर हल्द्वानी में वास्तव में 'शुद्धिकरण' किया गया था तो इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का सवाल है कि घटना पर कारवाई करने के बजाये राहुल गांधी के खिलाफ ही मामला क्यों दर्ज किया गया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए कानूनी कारवाई का सहारा ले रही है।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने बिना पूरे तथ्य जाने एक सामान्य

सफाई की घटना को जातिगत विवाद बना दिया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। पार्टी ने राहुल गांधी से अपने बयान पर स्पष्टीकरण और माफी की मांग की है।

इस पूरे मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एफआईआर दर्ज होने का मतलब राहुल गांधी दोषी साबित हो गए हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस को शिकायत, वीडियो, ब्यान और अन्य साक्ष्यों की जांच करनी होगी। जांच के बाद ही आगे की कानूनी कारवाई तय होगी।

हालांकि राजनीतिक स्तर पर मामला तेजी से गरम हो गया है। राहुल गांधी लगातार दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और संविधान के मुद्दे उठाते रहे हैं। कांग्रेस अब इस एफआईआर को भी इसी राजनीतिक लड़ाई से जोड़ रही है। शिमला का प्रदर्शन संकेत दे रहा है कि पार्टी इस मुद्दे को हिमाचल में भी जोर-शोर से उठाएगी।

दूसरी ओर भाजपा भी राहुल गांधी के ब्यान को निशाना बनाकर कांग्रेस पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में हल्द्वानी से शुरू हुआ विवाद अब शिमला तक पहुंच गया है और राहुल गांधी की एफआईआर भाजपा-कांग्रेस के बीच एक नए सियासी टकराव का मुद्दा बन गई है।

हिमाचल में 26 वर्ष बाद लॉटरी की वापसी पर सियासी टकराव तेज

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में करीब 26 वर्ष बाद लॉटरी व्यवस्था दोबारा शुरू करने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर वित्त विभाग की ओर से जारी लॉटरी टेंडर तत्काल वापस लेने की मांग की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार चंद करोड़ रुपये के राजस्व के लिए प्रदेश के युवाओं और परिवारों के भविष्य को जुए की मानसिकता की ओर धकेल रही है।

अनुराग ठाकुर ने 26 अगस्त को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में वित्त विभाग के ई-टेंडर का हवाला देते हुए कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी व्यवस्था के लिए बिक्री एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने सरकार से इस पूरी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होने कहा कि लॉटरी हिमाचल की वित्तीय समस्या का समाधान नहीं हो सकती और सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए स्थायी वित्तीय सुधारों पर ध्यान देना चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में लॉटरी पर प्रतिबंध किसी एक राजनीतिक दल की नीति नहीं रही, बल्कि इस मुद्दे पर लंबे समय तक दलगत सहमति बनी रही। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने 1999 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जब लॉटरी दोबारा शुरू हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2007 में इसे फिर बंद किया। बाद की सरकारों ने भी इस व्यवस्था को दोबारा लागू नहीं किया।

भाजपा सांसद ने दावा किया कि लॉटरी के कारण हिमाचल में कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों और युवाओं की आय तथा बचत प्रभावित हुई थी और कई परिवार आर्थिक संकट में पहुंचे। आज भी इसका सबसे अधिक प्रभाव निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर पड़ने की आशंका है।

अनुराग ठाकुर ने राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि 2026 में हिमाचल का कर्ज 1,10,010 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और ऋण-जीडीपी अनुपात 42 प्रतिशत से अधिक है। उनके अनुसार प्रस्तावित लॉटरी से सालाना करीब 100 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, जो राज्य की वित्तीय चुनौतियों के मुकाबले बेहद सीमित राशि है।

उन्होंने सरकार को जीएसटी अनुपालन मजबूत करने और डिजिटल एकीकरण बढ़ाने का सुझाव देते हुए दावा किया कि इन उपायों से सालाना 250 से 350 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकता है। उनका कहना है कि इससे लॉटरी के सामाजिक दुष्परिणामों के बिना राज्य की आय बढ़ाई जा सकती है।

इस बीच डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर और तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को जुए की लत की ओर धकेलने की तैयारी कर रही है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल जैसे शिक्षित और मेहनतकश प्रदेश में युवाओं के सामने रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है, न कि उन्हें आसान पैसे और जुए की मानसिकता की ओर ले जाने की। उन्होंने सरकार से लॉटरी का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि भाजपा इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाएगी।

चुनावी साल में खुलेंगी .....पृष्ठ 1 का शेष

जिम्मेदारी किसकी तय हुई?

आने वाला एक वर्ष इसी कसौटी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को परखेगा। कांग्रेस के पास सत्ता है और जांच एजेंसियों के माध्यम से पुराने मामलों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी। भाजपा के पास विपक्ष की भूमिका है और सरकार से जवाब मांगने का राजनीतिक अवसर भी।

लेकिन यदि कांग्रेस केवल भाजपा नेताओं पर कारवाई को उपलब्धि बताती रही और भाजपा केवल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही, तो जनता के सामने फिर वही पुराना सवाल खड़ा होगा कि चार्जशीट बहुत हुई, कारवाई कितनी हुई?

इसलिए अगले विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल की राजनीति में असली मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं होगा। मुकाबला यह भी होगा कि कौन आरोपों को सबूत, जांच और कानूनी परिणाम तक ले जाता है।

सुधीर शर्मा और जनक राज से जुड़े मामले इस बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भर हैं। आने वाले दिनों में यदि पुरानी फाइलें खुलती हैं, नई जांचें शुरू होती हैं और जमीन, संपत्ति, भर्ती तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कारवाई तेज होती है, तो हिमाचल का चुनावी माहौल असाधारण रूप से गर्म हो सकता है। और यदि सब कुछ आरोप-प्रत्यारोप, चार्जशीट और राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहा, तो चार साल की सत्ता और पांच साल की विपक्षी राजनीति के बीच जनता के सामने फिर वही सवाल रहेगा कि आखिर कारवाई हुई कहां?